

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक - 2026 राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक - 2026
2.	राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026
3.	द राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर बिल, 2026
4.	गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 2. अंश जैन और ऐश्वर्या इंवर (कोटा) 3. इंडो-इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2025-26 4. 'ज्वेल ऑफ इंडिया - भारत की शान, भारत का अभिमान' पुरस्कार 5. महर्षि दयानन्द सरस्वती राष्ट्र मंदिर (The Silicon Museum Of India) 6. 19वीं इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस (ISEC 2026)
6.	NIM और जिम एंड WS: माउंट एकांकागुआ
7.	'केरल' राज्य का नया नाम: "केरलम"
8.	नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री : रॉब जेटन
9.	'हिम-कनेक्ट': विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2026
10.	अभ्यास 'धर्म गार्जियन' (DHARMA GUARDIAN)
11.	अभ्यास 'वज्र प्रहार'
12.	ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक - 2026

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक - 2026



चर्चा में क्यों?

- 25 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक - 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक - 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।



मुख्य बिन्दु:

- **संशोधन** : प्रस्तावित विधेयकों के माध्यम से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-24 में संशोधन किया जाएगा।
- **संशोधन के प्रावधान** : जिन व्यक्तियों के दो से अधिक संतान हैं, वे पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे।

अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय :

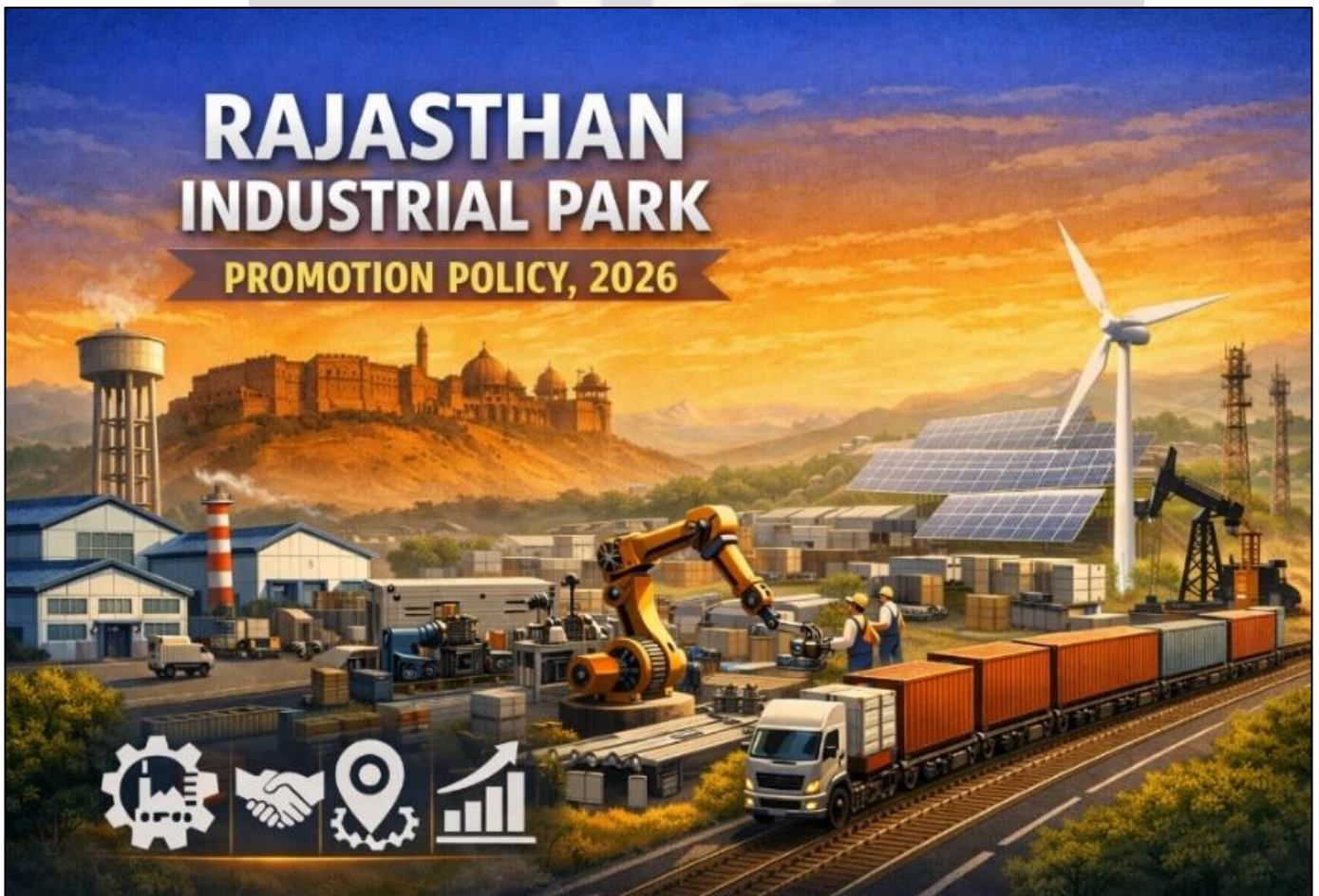
राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय:

- राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को 'राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय' से प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया।
- इससे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक-बीमा-NBFC एवं शेयर मार्केट से जुड़े वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) ठगी, झूठा दिवालियापन, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी या प्रवेश से संबंधित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी।
- साथ ही, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों का गठन, सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा।

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026

चर्चा में क्यों?

- 25 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026' का अनुमोदन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- प्रस्तावित नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार मॉडल निर्धारित किए गए हैं।
- मॉडल - A** : पूर्णतः रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास।

- **मॉडल - B** : 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर।
- **मॉडल - C** : संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था।
- **मॉडल - D** : पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)।
- नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी।
- **पूँजी अनुदान** : राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान देगी।
- **श्रेणी - I** : 100 एकड़ तक के पार्क हेतु अधिकतम ₹20 करोड़।
- **श्रेणी - II** : 100 से 250 एकड़ हेतु अधिकतम ₹30 करोड़।
- **श्रेणी - III** : 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिकतम ₹40 करोड़।
- **हरित विकास** : हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़/पार्क) का प्रावधान भी किया गया है।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (RIICO)
RIICO एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी स्थापना 28 मार्च, 1969 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम (RSIMDC) के रूप में की गई थी।
- 1 जनवरी, 1980 को इसे दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया:
 1. **RIICO** - राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
 2. **RSMDC** - राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम।

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



मुख्य कार्य:

- यह राज्य के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) का विकास करता है।
- एक वित्तीय संस्था के रूप में यह छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है।
- उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- वर्ष 2021-22 में, RIICO को COSIDICI द्वारा देश की सबसे श्रेष्ठ SIIDC (राज्य औद्योगिक विकास निगम) के रूप में सम्मानित किया गया।
- राज्य भर में 33 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं।

UTKARSH

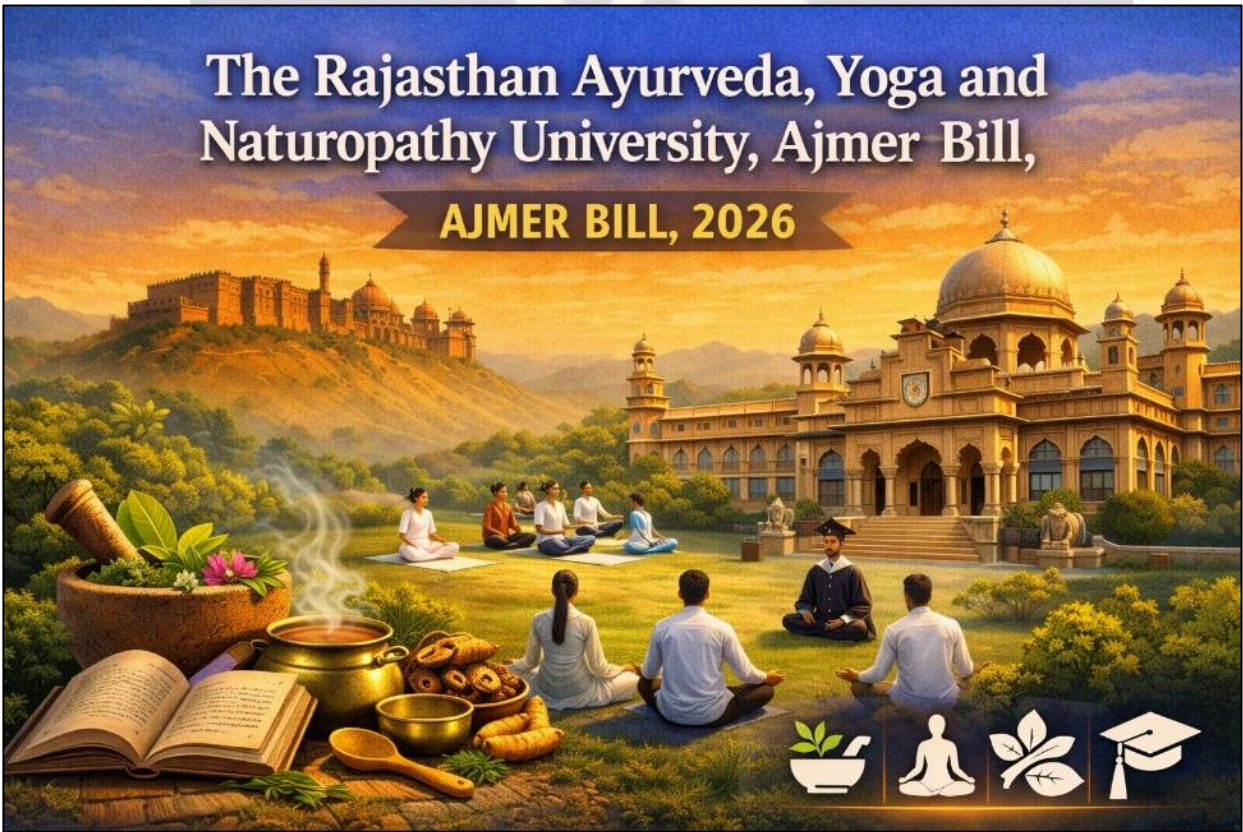
CIVIL
SERVICES

--:5:--

द राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर बिल, 2026

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 25 फरवरी, 2026 को सम्पन्न कैबिनेट बैठक में 'द राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर विधेयक-2026' के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- प्रस्तावित विधेयक में केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा।
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

--6--

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



- साथ ही, राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने में भी यह विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- राजस्थान का एकमात्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय : जोधपुर।
- राजस्थान आयुर्वेद निदेशालय : अजमेर।
- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) : जयपुर।
- राजस्थान में पहला पंचकर्म केंद्र - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र (CoE) : चाकसू (जयपुर)।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--7--

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना

चर्चा में क्यों?

- राज्य सरकार द्वारा 41 जिलों के एक-एक ब्लॉक में 'गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना' का संचालन किया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- 41 ज़िलों के चयनित ब्लॉक:

ब्लॉक	जिला	ब्लॉक	जिला
भिनाय	अजमेर	रामगढ़	अलवर
गढ़ी	बाँसवाड़ा	सिणधरी	बालोतरा
चौहटन	बाड़मेर	भूसावर	भरतपुर
करेड़ा	भीलवाड़ा	शाहबाद	बाराँ
बीकानेर	बीकानेर	सिकंदरा	दौसा
सैपऊ	धौलपुर	गलियाकोट	डूँगरपुर
नावा	डीडवाना-कुचामन	धमोतर	प्रतापगढ़
जालौर	जालौर	चाकसू	जयपुर
सम	जैसलमेर	झालरापाटन	झालावाड़
झुँझुनूँ	झुँझुनूँ	भादरा	हनुमानगढ़
मसूदा	ब्यावर	लाडपुरा	कोटा
बानसूर	कोटपूतली-बहरोड़	करौली	करौली
मेड़ता	नागौर	बाली	पाली

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



खंडार	सवाई माधोपुर	खंडेला	सीकर
पिंडवाड़ा	सिरोही	सादुलशहर	श्रीगंगानगर
उनियारा	टोंक	सराड़ा	सलूमबर
कोटड़ा	उदयपुर	कुंभलगढ़	राजसमंद
सेखाला	जोधपुर	आऊ	फलोदी
पहाड़ी	डीग	तिजारा	खैरथल-तिजारा
गंगरार	चित्तौड़गढ़	चूरू	चूरू
तालेड़ा	बूंदी		

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- इस योजना के माध्यम से राजस्थान में कुल 41 ब्लॉकों में लक्षित विकास कार्यक्रम संचालित कर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के जरिए सभी चिन्हित ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसकी मॉनिटरिंग के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाया गया है। योजना की विभिन्न स्तर पर निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय समितियाँ बनाई गई हैं।

--:9:--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



- **पुरस्कार** : योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को वार्षिक पुरस्कार राशि दी जाएगी।

स्थान	पुरस्कार राशि
प्रथम स्थान	50 लाख रुपये
द्वितीय स्थान	35 लाख रुपये
तृतीय स्थान	25 लाख रुपये

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP):

- केंद्र सरकार द्वारा अविकसित जिलों के उत्थान के लिए जनवरी, 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) 112 जिलों में शुरू किया गया।
- केंद्र सरकार एवं नीति आयोग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के पाँच जिले - बारों, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही शामिल है।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जिलों में आए सकारात्मक बदलाव, सफलता और विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने के लिए जनवरी, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 27 ब्लॉक शामिल है।

--:10:--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन स्थल : राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 25 फरवरी, 2026 को।■ उद्देश्य : राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 'बायो हब' के रूप में स्थापित करना।■ आयोजक : डॉ. बी. लाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) वनस्थली विद्यापीठ और राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से।■ मुख्य विषय : "BioE3 - Biotechnology for Economy, Environment & Employment"
2.	<p>अंश जैन और ऐश्वर्या झंवर (कोटा)</p> <ul style="list-style-type: none">■ कोटा के दो युवा उद्यमी अंश जैन और ऐश्वर्या झंवर ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया-AI इंपैक्ट समिट 2026' राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।■ ऐश्वर्या झंवर 'एकत्र' (Ekatra) स्टार्टअप की संस्थापक हैं, जो महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनसे इको-फ्रेंडली स्टेशनरी और अन्य उत्पाद बनवाती हैं। ऐश्वर्या को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ से मिलने का निमंत्रण मिला।■ अंश जैन ने इस समिट के दौरान अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म 'ICR' का प्रदर्शन किया।
3.	<p>इंडो-इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2025-26</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : 13 से 19 फरवरी, 2026 तक बाली, इंडोनेशिया में।■ राजस्थान के खिलाड़ी : राजस्थान की हर्षिता जुनवाल (जयपुर) और कुमकुम सोनी (चूरू) महिला टीम में जबकि हर्ष देतरवाल (चूरू) पुरुष टीम में।■ आयोजक : बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ एशिया और इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन फेडरेशन।■ भारतीय टीम का प्रदर्शन : मेजबान इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर सीरीज जीती।

4.	<p>'ज्वेल ऑफ इंडिया - भारत की शान, भारत का अभिमान' पुरस्कार</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जयपुर के 'लेट्स डिजाइन लाइफ' के संस्थापक सजीव सचदेव को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 'ज्वेल ऑफ इंडिया—भारत की शान, भारत का अभिमान' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।समारोह में भारत की वैश्विक विरासत और प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को समर्पित 'ज्वेल ऑफ इंडिया-भारत की शान, भारत का अभिमान' पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गर्जेन्द्र सिंह शेखावत ने किया।
5.	<p>महर्षि दयानन्द सरस्वती राष्ट्र मंदिर (The Silicon Museum Of India)</p> <ul style="list-style-type: none">22 फरवरी, 2026 को महर्षि दयानन्द सरस्वती राष्ट्र मंदिर में 'गाथा अमर बलिदानियों की' कार्यक्रम आयोजित किया गया।महर्षि दयानन्द सरस्वती राष्ट्र मंदिर (The Silicon Museum of India) नौलखा महल (उदयपुर) में स्थित है। यह संग्रहालय अमर बलिदानियों की गाथाओं और भारतीय संस्कृति को समर्पित है।यह वही स्थान है जहाँ महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' के लेखन को पूर्ण किया था।
6.	<p>19वीं इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस (ISEC 2026)</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : 19 से 21 फरवरी, 2026 तक IIS (डीमंड टू बी यूनिवर्सिटी), जयपुर।आयोजक : यह कॉन्फ्रेंस ACM इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के विशेष रुचि समूह (iSOFT) का वार्षिक कार्यक्रम है।मुख्य उद्देश्य : सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीनतम शोध, नवाचार और औद्योगिक प्रगति को साझा करने के लिए शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

NIM और जिम एंड WS: माउंट एकांकागुआ

चर्चा में क्यों?

- नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान (JIM एंड डब्ल्यूएस), पहलगाम के छह सदस्यीय दल ने दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे शिखर और एशिया के बाहर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर 22 फरवरी, 2026 को सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की।



मुख्य बिन्दु:

- चढ़ाई की शुरुआत: 5 फरवरी, 2026 को कर्नल हेम चंद्र सिंह के नेतृत्व में शुरू की थी।
- दल के सदस्य: संतोष कुमार, दीप बहादुर साही, विनोद गुसाई, नायब सिपाही भूपिंदर सिंह और हवलदार रमेश कुमार।

माउंट एकांकागुआ:

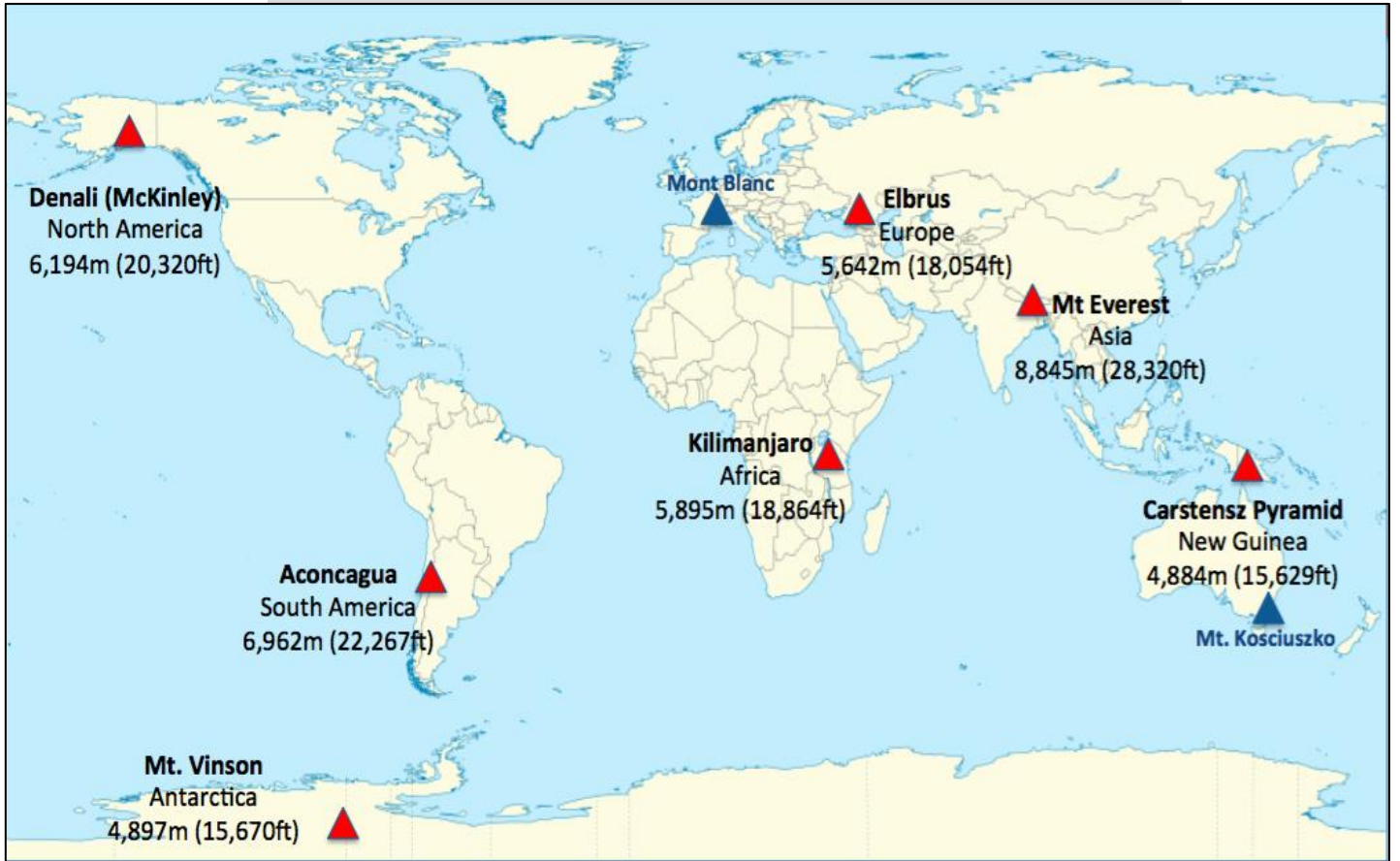


- **अवस्थिति:** अर्जेटीना की दक्षिणी एंडीज पर्वतमाला (दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट पर फैली हुई है) में स्थित है।
- यह स्थान पश्चिमी मेंडोज़ा प्रांत में, अर्जेटीना-चिली सीमा के निकट स्थित है।
- यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊँचा पर्वत है और एशिया के बाहर का सबसे ऊँचा पर्वत है।
- **एकांकागुआ पर्वत का निर्माण:** इस पर्वत का निर्माण भारी नाज़का प्लेट सबडक्शन नामक प्रक्रिया के माध्यम से दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धसने के कारण हुआ है।

-:14:-

विशेषताएं:

- ज्वालामुखीय उत्पत्ति का होने के बावजूद, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है।
- इसमें दो शिखर (उत्तर और दक्षिण) शामिल हैं जो क्रेस्टा डेल गुआनाको नामक एक पर्वतमाला द्वारा जुड़े हुए हैं।
- यह अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से बना एक वलित पर्वत है।
- पर्वत पर जलवायु क्षेत्र: विरल वनस्पति के साथ शुष्क और रेगिस्तानी जैसा, अल्पाइन रेगिस्तानी क्षेत्र और शिखर पर आर्कटिक जैसी स्थितियाँ।
- इस पर्वत में ग्लेशियर भी मौजूद हैं, जिनमें से वेंटिस्केरो होरकोनेस इन्फेरियर सबसे बड़ा है।



भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

'केरल' राज्य का नया नाम: "केरलम"



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2024 में केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राज्य का नाम बदलकर "केरलम" करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजा जाएगा।





मुख्य बिन्दु:

केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव:

- **पहली अनुसूची:** केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम बदलकर "केरलम" करने का निर्णय लिया।
- **आठवीं अनुसूची:** केरल विधानसभा ने विशेष रूप से अनुरोध किया कि संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सभी आधिकारिक भाषाओं में "केरलम" में बदल दिया जाए, जिससे पूर्ण भाषाई संगति सुनिश्चित हो सके।

संवैधानिक प्रावधान:

1. **अनुच्छेद-3; संसदीय अधिकार:** संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। तथा इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो जानी चाहिए।
2. **पहली अनुसूची:** भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय सीमाएं सूचीबद्ध हैं, जो भारत के राजनीतिक मानचित्र का कानूनी आधार बनती हैं।
 - यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद-1 और 4 से संबंधित है। अनुच्छेद-1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, और अनुच्छेद-4 संसद को राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें नामों, सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन शामिल है।

नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया:

- राज्य प्रस्ताव:** इस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य विधानसभा, नाम परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित करने के साथ होती है और उसे गृह मंत्रालय (MHA) को भेजती है।
- मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र:** गृह मंत्रालय अनुरोध की जांच करता है और रेल मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारत के रजिस्ट्रार जनरल जैसे विभिन्न हितधारकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाम परिवर्तन मौजूदा प्रशासनिक, भौगोलिक या सुरक्षा अभिलेखों के साथ टकराव न करे।
- प्रस्तुत:**
 - गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, विधेयक को संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - यदि विधेयक किसी राज्य के नाम या सीमाओं को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक का मसौदा संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना होगा।
- समयबद्ध प्रक्रिया:** राज्य विधानमंडल से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। संसद राज्य विधानमंडल के विचारों के प्रति बाध्य नहीं है।
- संसद से पारित:** विधेयक को पारित करने के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जिससे पहली अनुसूची में संशोधन होगा और इसे अनुच्छेद-368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति:** विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नाम परिवर्तन कानून बन जाता है।
 - उदाहरण: उत्तरांचल से उत्तराखंड (वर्ष 2007) और उड़ीसा से ओडिशा (वर्ष 2011)।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

'केरलम' शब्द:

- **शिलालेखीय साक्ष्य:** इस क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक शिलालेखीय प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेख द्वितीय (257 ईसा पूर्व) में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को "केरलपुत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है (चेरा राजवंश)।
- **"केरलम" शब्द की उत्पत्ति:** जर्मन विद्वान हरमन गुंडर्ट (जिन्होंने पहला मलयालम-अंग्रेजी शब्दकोश संकलित किया) के अनुसार, "केरलम" शब्द "चेरम" या "चेरालम" से विकसित हुआ है जो मूल शब्द "चेर" का अर्थ है "जोड़ना" और "अलम" का अनुवाद "भूमि या क्षेत्र" के रूप में होता है।
- **ऐक्य केरल आंदोलन:** वर्ष 1920 में मालाबार, कोच्चि और त्रावणकोर के मलयालम भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करने वाले हेतु एक संयुक्त राज्य की राजनीतिक आंदोलन था।
- **राज्य पुनर्गठन (वर्ष 1956):** स्वतंत्रता के बाद, सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर एक एकीकृत राज्य के निर्माण की सिफारिश की तथा 1 नवंबर, 1956 को (केरल पिरवी दिवस) मालाबार जिले और कासरगोड तालुक को एकीकृत करके आधुनिक राज्य का गठन किया गया, जबकि त्रावणकोर के कुछ दक्षिणी भागों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री : रॉब जेटन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, रॉब जेटन को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया।



मुख्य बिन्दु:

- शपथ:** जेटन को 23 फरवरी, 2026 को द हेग के हुइस टेन बॉश पैलेस में किंग विलेम-अलेक्जेंडर ने औपचारिक रूप से शपथ दिलाई।
- रॉब जेटन अपनी माइनॉरिटी सरकार के शपथ लेने के बाद नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे (समलैंगिक) प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं।
- पार्टी:** डेमोक्रेट्स 66 पार्टी (D66) ने विरोधी पॉपुलिस्ट गीर्ट वाइल्डर्स को हराया।

--:20:--

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

नीदरलैंड्स:



- **उपनाम:** हॉलैंड।
- **अवस्थिति:** उत्तर-पश्चिमी यूरोप का एक देश है, जिसके बाहरी इलाके कैरिबियन में हैं।
- **भाषा:** आधिकारिक भाषा डच है, और फ़्रिसलैंड प्रांत में वेस्ट फ़्रीज़ियन दूसरी आधिकारिक भाषा है। कैरिबियन इलाकों में डच, अंग्रेज़ी और पापियामेंटो आधिकारिक भाषाएँ हैं। नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है।
- रॉटरडैम का बंदरगाह यूरोप में सबसे व्यस्त है। शिफोल नीदरलैंड का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, और यूरोप में चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।

--:21:--

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



- दिसंबर, 2025 में भारत और नीदरलैंड्स ने संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति (JTIC) की स्थापना की हैं।

भारत-नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी:

- भारत और नीदरलैंड ने 'भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम' शुरू करके और ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान तथा शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन (MoU): ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) के मध्य।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:22:-

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

'हिम-कनेक्ट': विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2026

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (WSDS) के दौरान 25 से 27 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली में 'हिम-कनेक्ट' कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

The banner features logos for GPNHE, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, LIFE (Living India For Environment), TERI (The Energy and Resources Institute), and WSDS. The main text reads 'Him-CONNECT' and 'Connecting Himalayan Innovations with Start-ups & Industries'. Below the text is a collage of 12 images showing various innovations and activities in the Himalayan region, including people working on projects, machinery, and community gatherings.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Him-CONNECT

Connecting Himalayan Innovations with Start-ups & Industries

Showcasing NMHS-Supported Innovations from the Indian Himalayan Region

WSDS 2026 | 25th - 27th February 2026 | Shahjahan Hall, Taj Palace, New Delhi

--:23:--



मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** 'हिम-कनेक्ट' एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में कार्यरत शोधकर्ताओं को स्टार्टअप, निवेशकों और नीति निर्माताओं से जोड़ना है, ताकि उनके शोध परिणामों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।
- मंत्रालय के राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS) के तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्र के नाजुक परितंत्र के लिए विकसित 24 से अधिक प्रौद्योगिकियों, प्रोटोटाइपों, पेटेंटों और प्रायोगिक परियोजनाओं को हिम-कनेक्ट के दौरान प्रदर्शित किया गया।
- **प्रदर्शित किए गए प्रमुख नवाचार:** पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण, हाइड्रोपोनिक खेती के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग, रेशम उत्पादन अपशिष्ट को जलन निवारक मलहम में परिवर्तित करना, कम लागत वाले खनिजयुक्त जल शोधक, चीड़ की सुइयों पर आधारित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली, हिमालय के लिए विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल पुनः उपयोग समाधान और याक के दूध से बने पनीर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां।

विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2026 (WSDS):

- **शुरुआत:** वर्ष 2001 में दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन से हुई।
- **वर्ष 2026 का संस्करण (शिखर सम्मेलन की रजत जयंती):**
- **आयोजन:** 25 से 27 फरवरी, 2026 तक ताज पैलेस, नई दिल्ली
- **संस्करण:** 25वाँ
- **विषय:** "Transformations : Vision, Voices, and Values for Sustainable Development" (सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज और मूल्य)।
- **आयोजक:** द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI)।

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



मुख्य फोकस क्षेत्र:

- **जलवायु कार्रवाई और वित्त:** स्वच्छ ऊर्जा और हरित विनिर्माण (Green Manufacturing)।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs):** वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समीक्षा।
- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र:** पानी की सुरक्षा, अपशिष्ट-से-धन (Waste-to-Wealth), और टिकाऊ आजीविका।
- **रजत जयंती प्रकाशन:** TERI ने "विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (वर्ष 2001-2026): सतत विकास पर महत्वाकांक्षा और कार्रवाई के 25 संस्करण" नामक एक पुरालेख पॉकेटबुक भी जारी की।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:25:--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

अभ्यास 'धर्म गार्जियन' (DHARMA GUARDIAN)

📢 चर्चा में क्यों?

- 24 फरवरी, 2026 को भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JGSDF) के मध्य वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन (DHARMA GUARDIAN)' का 7वाँ संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ।



📌 मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** 24 फरवरी से 9 मार्च, 2026 तक।
- **शामिल इकाइयाँ:** इस संस्करण में दोनों पक्षों से 120-120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जम्मू-सैनिक सुरक्षा बल की ओर से 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल हैं।

--:26:--

Daily Current Affairs

Date : 26 February, 2026



- **उद्देश्य:** अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना।
- **अभ्यास की शुरुआत:** वर्ष 2018
- **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:**
- **भारत-जापान के अन्य सैन्य अभ्यास:** जिमेक्स (जापान-भारत समुद्री अभ्यास), शिन्यू मैत्री (हवाई अभ्यास), सहयोग काइजिन (तटरक्षक बल), मालाबार (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका)।
- **भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा:** भारत के प्रधानमंत्री ने 29-30 अगस्त, 2025 को 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की आधिकारिक कार्य यात्रा की। जिसके दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 2022 से भारत में जापान द्वारा पांच वर्षों में 5 ट्रिलियन येन के सार्वजनिक और निजी निवेश और वित्तपोषण के लक्ष्य रखा हैं।
- **18वां भारत-जापान रणनीतिक संवाद (नई दिल्ली; जनवरी, 2026):**
- **5 प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित:** सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स।
- भारत-जापान AI सहयोग पहल (JAI) के तहत "भारत-जापान AI रणनीतिक संवाद" की स्थापना की जाएगी।
- जापान संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2030 तक भारत से 500 अत्यधिक कुशल AI पेशेवरों को आमंत्रित करेगा।

--:27:--

अभ्यास 'वज्र प्रहार'

चर्चा में क्यों?

- भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' का 16वाँ संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।



मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** 24 फरवरी से 16 मार्च, 2026 तक।
- **पिछला संस्करण:** इस सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर, 2024 में अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया था।
- **शुरुआत:** वर्ष 2010
- **उद्देश्य:** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसके लिए पारस्परिक समन्वय, संयुक्त तथा विशेष अभियान रणनीतियों के आदान-प्रदान को सुदृढ़ किया जाएगा। यह अभ्यास पर्वतीय क्षेत्र में संयुक्त विशेष बल अभियानों के संचालन हेतु संयुक्त क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।
- **भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास:** प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों में युद्ध अभ्यास (सेना), कोप इंडिया (वायु सेना) और टाइगर ट्रायम्फ (त्रि-सेवाएं) शामिल हैं तथा दोनों देश मालाबार, रिमपैक और रेड फ्लैग जैसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासों में भी सहयोग करते हैं।

ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज

चर्चा में क्यों?

- 23 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया गया।



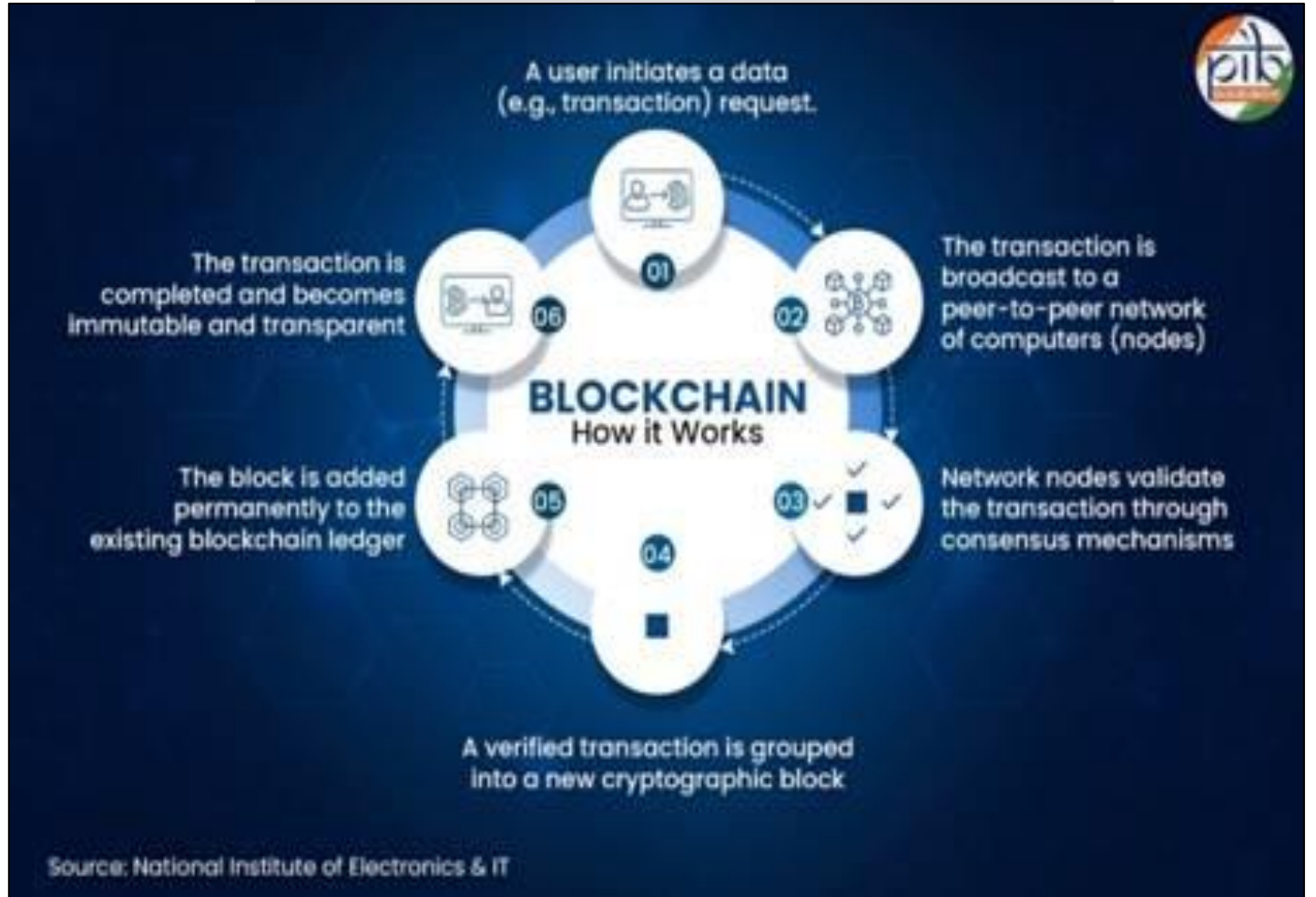
मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका मकसद भारतीय स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल गवर्नेंस समाधानों को प्रस्तुत करने और उनका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **शुरुआत:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)।

- **लक्ष्य:** सरकारी उपयोग के मामलों के लिए नियामक नियंत्रण और सुरक्षा (विश्वास, लेखापरीक्षा योग्यता और छेड़छाड़-रहित रिकॉर्ड) को प्राथमिकता देते हुए, अनुमति-आधारित ब्लॉकचेन समाधान विकसित करना है।
- **केंद्रित:** ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज ई-प्राप्ति, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बिजली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), भूमि अभिलेख, पर्यावरण और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शासन और सेवा वितरण चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

ब्लॉकचेन:



- ब्लॉकचेन एक वितरित, पारदर्शी, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय डेटाबेस है जो रिकॉर्ड या लेन-देन के बहीखाते की तरह काम करता है, छेड़छाड़-रोधी है और कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर सुलभ है।

ब्लॉकचेन के प्रकार:

1. **सार्वजनिक ब्लॉकचेन:** इस नेटवर्क में, सभी नोड्स रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, लेन-देन सत्यापित कर सकते हैं, कार्य-प्रमाणन कर सकते हैं और नए ब्लॉक जोड़ सकते हैं।
 2. **निजी ब्लॉकचेन:** यह एक अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन है, जो किसी संगठन के भीतर चुनिंदा प्रतिभागियों तक सीमित है। नियंत्रक संस्था सुरक्षा, प्राधिकरण और पहुंच के स्तर निर्धारित करती है, जो इसे सरकारी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है। डिजाइन के अनुसार, यह प्रतिभागियों के बीच विश्वास बढ़ाता है और साथ ही डेटा गोपनीयता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है।
 3. **कंसोर्टियम ब्लॉकचेन:** इस नेटवर्क में, ब्लॉकचेन अर्ध-विकेंद्रीकृत होता है, जिसे साझा डेटा प्रबंधन और सत्यापन के लिए कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है।
 4. **हाइब्रिड ब्लॉकचेन:** यह सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन का मिश्रण है जो चुनिंदा डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है।
- **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF):** NBF की शुरुआत मार्च, 2021 में ₹64.76 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ हुई थी। 4 सितंबर, 2024 को अपने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया, NBF को अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोगों के विकास और परिनियोजन में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है।